उपलब्धि : यूपी की ओडीओपी योजना को अपनाएगा देश

लखनऊ | विशेष संवाददाता

केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट) यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को बड़ी तरजीह दी गई है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने इसे बागवानी के क्षेत्र में पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। इससे सहारनपुर से लेकर प्रयागराज तक आम, अमरूद उगाने वाले छोटे किसानों की आय बढ़ाने में मदद तो मिलेगी ही वहीं किसान ट्रेन की शुरुआत के अलावा दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा देने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी पंख लगने की उम्मीद बढ़ी है।

फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए विशेष ट्रेनों का सोनभद्र से सहारनपुर तक के किसानों को लाभ मिलेगा। पंप सेटों के डीजल-केरोसीन पर निर्भरता घटाने की तैयारी और सौर ऊर्जा पर जोर का भी सर्वाधिक फायदा यूपी के तीन करोड़ किसानों को मिलेगा।

किसानों को राहत मिलेगी

- बागवानी में ओडीओपी योजना से छोटे किसानों को मिलेगी राहत
- दुग्ध उत्पादक व किसानों को लाभ से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

हर जिले में और अधिक जनऔषधि केंद्र खोलने की बात कही गई है। लिहाजा, यूपी को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के आठ सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया जा सकेगा।

दूध उत्पादकों को भी फायदा: यूपी दूध उत्पादन में पहले से ही नंबर एक पर है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 2025 तक दूध उत्पादन दुगुना करना है यानी देश में दूध उत्पादन 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करना है। इसमें भी यूपी की भूमिका अहम होगी।

प्रदेश को पिछली बार से 12.22 हजार करोड़ ज्यादा

मंदी का असर केंद्रीय करों पर भी दिख रहा है। वर्ष 2020-21 में केंद्रीय करों का जो अनुमान किया गया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश को इन करों से 140611.48 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में तय 128388.21 करोड़ रुपये के मुकाबले 12223.27 करोड़ रुपये अधिक है।

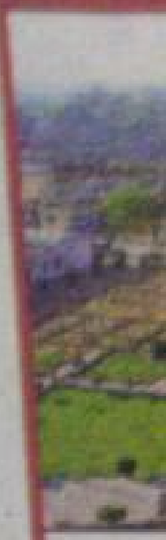

Hindustan page 1- 3/2/20